



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

49-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 12, 2025 (PHALGUNA 21, 1946 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 12th March, 2025

No. 5-HLA of 2025/9/4755.— The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 5-HLA of 2025

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2025.
2. In sub-section (5) of section 53 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, for the words “whichever is earlier” existing at the end, the words “whichever is later” shall be substituted.

Short title.

Amendment of section 53 of Haryana Act 11 of 1994.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the interest of justice, adequate opportunity of hearing is required to be afforded to a person against whom an enquiry is conducted into a complaint. A reasonable time is required to conclude the enquiry and assess the loss, waste or mis-application to gram fund. Therefore, it is necessary to increase the time period of a notice being issued to a person to explain his position for the loss, waste or mis-application of gram fund, so that they may be made more responsible and accountable.

Hence this Bill.

KRISHAN LAL PANWAR,
Development and Panchayats Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 12th March, 2025.

DR. SATISH KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 5 एच.एल.ए.

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।
2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 53 की उप-धारा (5) में, विद्यमान "जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "जो भी बाद में हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संक्षिप्त नाम।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 53 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जिस व्यक्ति के खिलाफ किसी शिकायत की जांच की जाती है, न्याय के हित में, उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। जांच पूरी करने और ग्राम निधि के नुकसान, बर्बादी या दुरुपयोग का आकलन करने के लिए उचित समय की आवश्यकता होती है। इसलिए, ग्राम निधि के नुकसान, बर्बादी या दुरुपयोग के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को जारी किए जाने वाले नोटिस की समय अवधि को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि उन्हें अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जा सके।

अतः यह विधेयक है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 12 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।